सार्वजनिक शिक्षा का निजीकरण क्यों ?

राजपाल मित्ताथल

केंद्र व हरियाणा की सरकार प्राथमिक व उच्च शिक्षा का व्यावसायिकरण, नीजिकरण व भगवाकरण कर रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पर जनता व शिक्षाविदों को गुमराह करके चोर दरवाजे से शिक्षा विभाग में शिक्षा का निजीकरण, भगवाकरण, केंद्रीयकरण किया जा रहा है नव उदारीकरण नीतियों को लगातार लागू करते हुए देश व प्रदेश की सरकार शिक्षा को जनमानस से दूर करने के रास्ते पर चल रही है सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए सरकार कोई ठोस योजना नहीं बना रही बल्कि उल्टा शिक्षा के बजट में लगातार कटौती कर रही है हालांकि शिक्षा पर जीडीपी का 6%, केंद्रीय बजट का 10% ओर राज्य बजट का 30% खर्च होना चाहिए लेकिन वर्ष 2018 में शिक्षा का बजट घटाकर जीडीपी का 0.45 और केंद्रीय बजट का 3.48% किया है जो कि 'ऊंट के मुंह में जीरे% के समान है।

7वें वेतन आयोग में संशोधन के नाम पर केन्द्रिय विश्वविद्यालयों को एमएचआरडी ने स्पष्ट कहा कि 30 प्रतिशत धन संग्रह स्वयं उत्पन्न किया जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा का कम बजट लागू करके सरकार रोजगार व गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा के अवसर खत्म कर रही है। रोजगार के अवसर खत्म होंगे तो शिक्षा का स्तर भी नीचे जाएगा। प्राइवेट विद्यालयों को तवज्जो देने के लिए वर्तमान सरकार ने शिक्षा बजट में कटौती के साथ-साथ हरियाणा में 1568 प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए हैं। पहली बार वर्ष 2018 - 20 के लिए जेबीटी शिक्षण संस्थानों में हरियाणा सरकार ने दाखिले ही बंद कर दिए हैं तथा दो शिक्षण संस्थान (बाइट) भी बंद कर दी हैं। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में 19100 जेबीटी छात्र-छात्राओं को दाखिले शुरू कर दिए हैं। जिनकी फिस 26,000 से बढ़ा कर 40,000 कर दी है।सरकारी शिक्षण संस्थानों में केवल 400 छात्र-छात्रा ही दाखिला ले सकेंगे। प्राइवेट नीजि शिक्षण संस्थानों का देश में कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसे शिक्षण संस्थानों को फाईलो के आधार पर ही अच्छे शिक्षण संस्थानों का दर्जा देकर 1000 करोड़ की सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसका पूरे देश में कोई शिक्षण संस्थान ही नहीं है हरियाणा में भी करोड़ों का बजट सक्षम करने के नाम पर अपने चहेतों की एनजीओ को बांटा जा रहा है। हरियाणा में देश स्तर पर मानी गई संस्था एससीईआरटी गुड़गांव से अध्यापकों को दी जाने वाली ट्रेनिंग का बजट व ट्रैनिंग का कार्य कुरुक्षेत्र की प्राईवेट संस्था जयराम विद्यापीठ को दे दिया गया है।

हर रोज शिक्षा विभाग में नए-नए फरमान सुनाए जाते हैं। शिक्षा सुधार की आड में शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण किया जा रहा है शिक्षा विभाग में अलग-अलग नामों से कच्ची भर्तियाँ की जा रही हैं। आज अकेले शिक्षा विभाग में कंप्यूटर टीचर,अतिथि अध्यापक,एले, लाइब्रेरियन,मल्टी पर्पस वर्कर, मिड डे मील ,पार्ट टाइम स्वीपर, चौकीदार, ब्यूटीशियन, सिम, एबीआरसी, बीआरपी आदि अनेक अनियमित कर्मचारियों व शिक्षको की भर्ती की गई है जो कि शिक्षा की बेहतरी व युवाओ के सपनो का शोषण ही करती है। सार्वजनिक शिक्षा के लिए सरकारी शिक्षा व स्थाई नियुक्ति का प्रबंध होना जरूरी है।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी घपलों का अड्डा बन गया है। बोर्ड ने बिना कोई कार्य किए अभिनव दृश्य, सॉफ्टवेयर समाधान के नाम पर प्राइवेट कम्पंनियों को भुगतना कर दिया। बोर्ड अध्यक्ष के निवास स्थान हिसार के एक कमरे को कैंप कार्यालय के नाम पर लाखों रुपये रिनोवेशन पर खर्च करने, बिजली पानी के भुगतान, सभी फार्मों जिसे एनआईसी 2.60 रुपये में करती थी, उससे छीनकर 5 गुणा रेट बढ़ाकर अपनी चहेती कंपनियों को 12.4 प्रति फार्म प्रति बच्चा में देकर बच्चों को लूटने, दसवीं, बारहवीं, जेबीटी, एचटेट के एनरोलमेंट, परीक्षा, पुनः मूल्यांकन, प्रैक्टिकल, माईग्रेशन में 2 से 10 गुणा तक की बढ़ोतरी करने का कार्य किया। एचटेट में 52180000 रुपये सीसीटीवी कैमरों का किराया, 14661000 मैटल डिटैक्टर फिशर्कीग मशीन (543केन्द्र) किराया, 20470000 रुपये जैमर के किराये का भुगतान किया गया है जबकि लगभग इतनी ही कीमत में ये सभी मशीनें मोल मिल सकती है।

हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है। सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था बनाने में सरकार नाकाम हुई है। विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मूलभूत सुविधाओं का होना अति आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। हरियाणा में प्राईमरी विद्यालयों की संख्या 8705, मिडल विद्यालयों की संख्या 2367, उच्च विद्यालयों की संख्या 1269 तथा सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों की संख्या 1971 है। प्राईमरी व मिडल विद्यालयों की बात करें तो यहां स्वीपर, चपड़ासी, चौकिदार, माली, क्लर्क व अग्रेजी अध्यापक आदि का एक भी पद स्वीकृत नहीं है। यदि ये पद स्वीकृत कर दिए जाएं तो अकेले प्राइमरी - मिडल विद्यालयों में 55350 युवाओं को रोजगार मिल सकता है। यहीं हाल उच्च और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों का है। यहां भी चतुर्थ श्रेणी के 12173 पद स्वीकृत है लेकिन 5262 पद यहां भी रिक्त पड़े हैं इनके अलावा क्लर्क के भी हजारों पद रिक्त है। 50 हजार से भी ज्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक दो - दो विषयों को जोड़कर एक ही अध्यापक को पढ़ाने के लिए बाध्य किया गया है। संस्कृत अध्यापक संस्कृत- हिंदी, गणित अध्यापक गणित - विज्ञान और सामाजिक अध्ययन वाला अध्यापक सामाजिक और अंग्रेजी विषयों को पढाएगा। सरकार ने यहां भी 7100 पदों को समाप्त कर दिया। ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। अब सार्वजनिक शिक्षा के लिए शिक्षक को शिक्षक की भूमिका निभाने के लिए जनता के तमाम हिस्सों में जाकर आम गरीब - मजदूर - किसान के बच्चों से छिनी जा रही शिक्षा को बचाने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। क्योंकि सार्वजनिक शिक्षा ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है तथा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त है।शिक्षा को बाजार की वस्तु बना दिया गया है।जो आम जनता के हित में कभी भी नहीं हो सकता।

अवैध गैस्ट हाउस: अब चलेगा सर्वे करने व चिन्हित करने का ड्रामा

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बड़ी छाती ठोक कर सेक्टर वासियों के सामने कहते हैं कि रिहायशी मकानों में अवैध गैस्ट हाउसों का धंधा नहीं चलने दिया जायेगा। उनके इस छातीठोक ऐलान के महीनों बाद भी किसी गैस्ट हाउस के विरुद्ध कोई कार्यवाही आज तक भी नहीं हुई क्योंकि पूरा शासन-प्रशासन हरामखोरी व रिश्वतखोरी में आकंठ डूबा पड़ा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते कोई सरकारी अधिकारी काम करना ही चाहता, वे केवल वही काम करते हैं जिसकी उन्हें मोटी 'फ़ीस' मिलती है।

उक्त अवैध गैस्ट हाउसों को लेकर अब कहा जा रहा है कि सम्बन्धित विभागों की टीमें सर्वे करके उनका पता लगा कर उन्हें चिन्हित करेंगी और उसके बाद सीलिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी। वास्तव में सर्वे करके चिन्हित करने का तो केवल टाइम पास करने के लिये एक ड्रामा मात्र है; क्योंकि 'हूडा' नगर निगम व पुलिस आदि सभी विभागों को हर गैस्ट हाउस का खूब अच्छे से पता है। कोई भी अवैध धंधा इनकी सहमती के बिना चल ही नहीं सकता। इतना ही नहीं सभी विभागों के सम्बन्धित अधिकारी बाकायदा इन गैस्ट हाउसों में नियमित आते-जाते हैं और 'हफ़्ता' वसूली भी करते हैं।

'मज़दूर मोर्चा' के साथ-साथ कुछ अन्य अखबारों ने भी बाकायदा इन गैस्ट हाउसों के बारे में विस्तार से प्रकाशित किया है। क्षेत्र में रहने वाले निवासियों ने बाकायदा लिखित शिकायतें भी सम्बन्धित अधिकारियों को कई-कई बार दे रखी हैं। ऐसे में सर्वे करके चिन्हित करने की आवश्यकता कहां रह जाती है? दरअसल हरामखोरी पर तुले रिश्वतखोर अधिकारी अपनी लूट कमाई को जैसे-तैसे कुछ और समय तक बनाये रखने के लिये ही इस तरह की नाटकबाजी कर रहे हैं। उनकी कोई मंशा नहीं है कि इस अवैध कारोबार को बंद कराया जाय। यदि सरकार नाम की कोई चीज़ है और उसमें थोड़ा बहुत दम व शर्म बकाया है तो गैस्ट हाउस बंद कराने से पहले, इनको चलवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके उन्हें ठिकाने लगाये। यदि सरकार ऐसा कर पाये तो आईंदा कोई भी अधिकारी अपने क्षेत्र में इस तरह के धंधे कभी पनपने नहीं देंगे।

इन हालात में मंत्री जी को कोई बयान ठोकने से पहले अपनी व अपनी सरकार की औकात का सही-सही आंकलन जरूर कर लेना चाहिये।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे का विदेशों में काले धन का कारखाना : 'कैरवां' की रिपोर्ट

रवीश कुमार

कौशल श्रॉफ नाम के एक खोजी पत्रकार ने अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और केमैन आइलैंड से दस्तावेज़ जुटाकर डोभाल के बेटों के काले को सफेद करने और भारत के पैसे को बाहर भेजने के कारोबार का खुलासा कर दिया है.

डी कंपनी का अर्थ अभी तक दाऊद इब्राहीम का गैंग ही होता था, लेकिन भारत में एक और 'डी' कंपनी आ गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और उनके बेटों विवेक और शौर्य के कारनामों को उजागर करने वाली 'कैरवां' पत्रिका की रिपोर्ट में यही शीर्षक दिया गया है. साल दो साल पहले हिन्दी के चैनल दाऊद को भारत लाने के कई प्रोपेगैंडा प्रोग्राम करते थे, उनमें डोभाल को नायक की तरह पेश किया जाता था. किसने सोचा होगा कि जज लोया की मौत पर 27 रिपोर्ट छापने वाली 'कैरवां' पत्रिका 2019 की जनवरी में डोभाल को 'डी' कंपनी का तमगा दे देगी.

कौशल श्रॉफ नाम के एक खोजी पत्रकार ने अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और केमैन आइलैंड से दस्तावेज़ जुटाकर डोभाल के बेटों की कंपनी का खुलासा किया है. 'कैरवां' पत्रिका के अनुसार ये कंपनियां हेज फंड और ऑफशोर के दायरे में आती हैं. टैक्स हेवन वाली जगहों में कंपनी खोलने का मतलब ही है कि संदिग्धता का प्रश्न आ जाता है और नैतिकता का भी. यह कंपनी 13 दिन बाद 21 नवंबर 2016 को टैक्स केमन आइलैंड में विवेक डोभाल अपनी कंपनी का पंजीकरण कराते हैं. कैरवां के एडिटर विनोद होजे ने ट्वीट किया है कि नोटबंदी के बाद विदेशी निवेश के तौर पर सबसे अधिक पैसा भारत में केमैन आइलैंड से आया था. 2017 में केमैन आइलैंड से आने वाले निवेश में 2,226 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी. अब इसका मतलब सीधे भ्रष्टाचार से है या महज़ नैतिकता से.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटे विवेक डोभाल भारत के नागरिक नहीं हैं, इंग्लैंड के नागरिक हैं, और सिंगापुर में रहते हैं, और GNY ASIA Fund के निदेशक हैं. केमैन आइलैंड, टैक्स चोरों के गिरोह का अड्डा माना जाता है. कौशल श्रॉफ ने लिखा है कि विवेक डोभाल यहीं 'हेज फंड' का कारोबार करते हैं. BJP नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे शौर्य और विवेक का बिज़नेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. रिपोर्ट में कुछ जटिल बातें भी हैं, जिन्हें समझने के लिए बिजनेस अकाउंट को देखने की तकनीकि समझ होनी चाहिए. 'कैरवां' की रिपोर्ट में विस्तार से पढ़ा जा सकता है.

2011 में अजित डोभाल ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि टैक्स चोरी के अड्डों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके ही बेटे की कंपनी का नाम हेज फंड और ऐसी जगहों पर कंपनी बनाकर कारोबार करने के मामले में सामने आता है. विवेक डोभाल की कंपनी के निदेशक हैं डॉन डब्ल्यू ईबैंक्स और मोहम्मद अलताफ मुस्लियाम. ईबैंक्स का नाम पैराडाइज़ पेपर्स में आ चुका है. ऐसी कई फर्ज़ी कंपनियों के लाखों दस्तावेज़ जब लीक हुए थे, तो 'इंडियन एक्सप्रेस' ने भारत में पैराडाइज़ पेपर्स के नाम से छापा था. उसके पहले इसी तरह फर्ज़ी कंपनियां बनाकर निवेश के नाम पर पैसे को इधर से उधर करने का गोरखधंधा पनामा पेपर्स के नाम से छपा था. पैराडाइस पेपर्स और पनामा पेपर्स दोनों में ही वॉकर्स कॉरपोरेट लिमिटेड का नाम है, जो विवेक डोभाल की कंपनी की संरक्षक कंपनी है.

'कैरवां' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि विवेक डोभाल की कंपनी में काम करने वाले कई अधिकारी शौर्य डोभाल की कंपनी में भी काम करते हैं. इसका मतलब यह हुआ है कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क चल रहा है. इनकी कंपनी का नाता सऊदी अरब के शाही खानदान की कंपनी से भी है. भारत की गरीब जनता को हिन्दू-मुस्लिम परोसकर सऊदी मुसलमानों की मदद से धंधा हो रहा है. वाह! मोदी जी, वाह!

हिन्दी के अखबार ऐसी रिपोर्ट सात जन्म में नहीं कर सकते. उनके यहां संपादक चुनावी और जातीय समीकरण का विश्लेषण लिखने के लिए होते हैं. पत्रकारिता के हर छात्र को 'कैरवां' की इस रिपोर्ट का विशेष अध्ययन करना चाहिए. देखना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके बेटों का काला धन बनाने का कारखाना पकड़ने के लिए किन-किन दस्तावेज़ को जुटाया गया है. ऐसी खबरें किस सावधानी से लिखी जाती हैं. यह सब सीखने की बात है. हम जैसों के लिए भी. मैंने भी इस लेवल की एक भी रिपोर्ट नहीं की है. डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं. इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति NDTV उत्तरदायी नहीं है. इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं. इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार NDTV के नहीं हैं, तथा NDTV उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है.

आश्चर्य क्या, डोभाल एनएसए किस पीएम का है

1. **जो आदमी प्रधानमंत्री होकर तीन का पहाड़ा नही जानता हो।**
2. **जो आदमी प्रधानमन्त्री होकर विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रगान बजते समय आगे चल देता हो और उसे विदेशी लोग हाथ पकड़ कर रोकते हो।**
3. **जो आदमी प्रधानमन्त्री होकर नारियल और पाइनएप्पल में फर्क नही जानता हो।**
4. **जिस आदमी को प्रधानमंत्री होकर भी यह न पता हो कि देश की जनसंख्या सबा सौ करोड़ है या छः सौ करोड़ ।**
5. **जो आदमी प्रधानमंत्री होकर यह झूठ बोलता हो कि नेहरू जी सरदार पटेल की अंत्येष्ठि में नही गए ।**
6. **जो आदमी प्रधानमन्त्री होकर भी यह गप बोले कि विवेकानंद जी गुरु गोविंद सिंह जी और संत कवीर एक साथ बैठ कर परिचर्चा किया करते थे।**
7. **जो आदमी देश का प्रधानमंत्री होकर भी बिन बुलाए पाकिस्तान जा सकता हो ।**
8. **जो आदमी प्रधानमन्त्री होकर भी देश को झूठी एम् ए की डिग्री दिखा सकता हो।**
9. **जो आदमी प्रधानमंत्री होकर महिला सशक्तिकरण की बात करता हो और खुद की पत्नी का बिना क़ानूनी रूप से अलग हुए परित्याग कर चुका हो ।**
10. **जो आदमी प्रधानमंत्री होकर भी मुझे फांसी पर लटका देना , मुझे लात मार कर बाहर कर देना , मेरे मुंह पर थूक देना जैसी अमर्यादित भाषा बोलता हो।**

REMEMBRANCE

On the 16th Death Anniversary of

Dy. S.P. NIRANJAN SINGH

You will always remain in our hearts.

Deeply Remembered by :

Sumitra Devi - Wife
Satish Kumar, Anil Kumar - Sons
Nirmal, Nisha - Daughters
Dr. S.S. Beniwal, S.S. Sheokand - Sons-in law
Grand Sons & Daughters -
Nidhi, Nakul, Yajur, Bobby, Divyejeet, Akhil & Vidushi